

रिपोर्टयोग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय न्यायपालिका

सिविल अपीलीय संख्या (एस) ऑफ _____ 2023

[एसएलपी (सिविल) नंबर (स).15774 ऑफ 2023 से उत्तपन होती हुई।

देव गुप्ता

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य

..... उत्तरदातागण (गण)

निर्णय

S.RAVINDRA BHAT,J.

1. विशेष अनुमति प्रदान करी गयी। यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय¹ के एक आदेश को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक उम्मीदवार को 2 प्रतिशत खेल कोटे के तहत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पात्रता शर्त (योग्यता परीक्षा में) के रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत कुल अंकों को लागू करने पर सवाल उठाया गया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि इस तरह की पात्रता शर्त के अचानक लागू होने से कोटा का उद्देश्य ही विफल हो गया और परिणामस्वरूप यह मनमाना था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अधिकारियों को एक मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता थी।

1 दिनांकित 14.07.2023 में सी.डब्ल्यू.पी संख्या 14594 ऑफ 2023

2. तकनीकी शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन (इसके बाद "यूटीसी") ने दिनांक 07.01.2016 के पत्र द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय") को 2016-2017 (इसके बाद "जोसा" के रूप में संदर्भित) से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय परामर्श प्रणाली के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने की मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश ने लगातार इस प्रक्रिया का पालन किया था और चंडीगढ़ के भीतर संस्थानों में प्रवेश इसके नियमों द्वारा विनियमित किया जाता था। "जोसा" के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के नियम 07.06.2023 को एक विवरणिका के माध्यम से जारी किए गए थे। वे नियम केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों पर लागू होते हैं, जिनमें प्रतिवादी भी शामिल हैं-जिनके नाम का उल्लेख क्रम संख्या 25 में मिलता है।

3. इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रदान की गई पात्रता मानदंड और वही नीचे दिया गया है:

"1. बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त किए होने चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कुल अंक कम से कम 65 प्रतिशत होने चाहिए।"

प्रतिवादी ने चार आरक्षित श्रेणियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश विवरणिका जारी की। खेल उम्मीदवारों के लिए लागू पात्रता मानदंड का उल्लेख खंड 1 (बी) में किया गया था जिसे नीचे निकाला गया है:

"बी. उम्मीदवार ने संबंधित स्ट्रीम और बोर्ड की बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।"

4. सत्रह (17) सीटें खेल श्रेणी (2 प्रतिशत कोटे के तहत) के लिए निर्धारित की गई थीं। विश्वविद्यालय को कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए-जिनमें से 28 आवेदकों ने 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा किया। शेष छह आवेदनों में अपीलकर्ता के आवेदन शामिल थे जिन्होंने मूल 75 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए थे। इसके अलावा, खेल श्रेणी की कुल 17 सीटों में से 16 सीटें पहले ही योग्य उम्मीदवारों को आवंटित

की जा चुकी हैं और सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग शाखा में आज की तारीख तक केवल 1 सीट खाली हुई है, जिसके लिए 10.08.2023 को काउंसलिंग आयोजित किया जाना है। यह स्वीकार किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू खेल नीति पहले प्रकाशित की गई थी।

5. प्रवेश के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों को कैसे वर्गीकृत किया जाना था, यह इंगित करने के लिए विवरणिका में कई श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें खेल कोटा के उम्मीदवार शामिल नहीं थे। वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने प्रवेश के उद्देश्यों के लिए जोसा का पालन किया; हालाँकि, खेल कोटा श्रेणी को जोसा कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। इसी तरह तीन अन्य श्रेणियों यानी कश्मीरी प्रवासियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया था।

6. 24.06.2023 पर विवरणिका के प्रकाशन के बाद, प्रतिवादी ने एक विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन करने का आह्वान किया। अपीलकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष शिकायत की कि 27.06.2023 को पात्रता की शर्त अवास्तविक रूप से अधिक थी। कोई जवाब नहीं मिलने पर, उन्होंने एक रिट याचिका दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

7. श्री पी.एस पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की न्यूनतम पात्र शर्त, खेल कोटा प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देती है क्योंकि यह मानता है कि अन्य सामान्य उम्मीदवारों की तरह खिलाड़ियों के पास भी शैक्षणिक उत्कृष्टता की डिग्री होगी जो सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया था कि खेलों में भाग लेने वालों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए और 2 प्रतिशत कोटा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि जहां तक खेल कोटा उम्मीदवारों का संबंध है, विवरणिका स्वयं एक अंतर बताती है क्योंकि ऐसे उम्मीदवार जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए आवेदन करने के योग्य हैं; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को पात्र माने जाने के लिए 65 प्रतिशत अंक

होने चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि अतीत में भी, केंद्र शासित प्रदेश ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए खेल कोटे में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए उच्च मानदंड नहीं लगाए थे।

8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अतीत में, खेल कोटा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था कि अंतर-से रैंकिंग निर्धारित करने के उद्देश्य से किन निर्दिष्ट खेलों का वर्गीकरण किया जाएगा और इसके अलावा, आयोजनों के प्रकार, और पात्रता और मूल्यांकन मानदंड का मार्गदर्शन करने वाली शर्तें (जैसे कि संबंधित खेलों में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या, भागीदारी का स्तर, यानी संबंधित नियामक बोर्ड या संगठन/महासंघ, आदि द्वारा आयोजित जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम)। ये खेल उम्मीदवारों की अंतर-श्रेणी रैंकिंग के निर्धारण दोनों का मार्गदर्शन और विनियमन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग शैक्षणिक योग्यता के बजाय संबंधित खेलों में उच्च दक्षता प्राप्त करते हैं, उन्हें विधिवत समायोजित किया जाए।

9. प्रतिवादी की ओर से पेश हुए श्री संचार आनंद ने इस अदालत से हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि एडमिशन लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी, केंद्र शासित प्रदेश ने योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत न्यूनतम कट-ऑफ के प्रासंगिक मानदंड पर जोर दिया था और खेल कोटे के लिए 75 प्रतिशत न्यूनतम मानदंड को उचित ठहराते हुए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए एक नोट की ओर इशारा किया था। यह तर्क दिया गया कि 2017-18 के लिए, खेल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक 60 प्रतिशत थे, इसे 2018-19 और 2019-20 वर्षों के लिए बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस तरह के मानदंड के आग्रह में स्वाभाविक रूप से मनमाना या भेदभावपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान मामले में भी प्राप्त 34 आवेदनों में से 28 ने 75 प्रतिशत की सीमा को पूरा किया और एक (17 में से) को छोड़कर सभी सीटें उनके द्वारा भरी गई थीं।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि खेल कोटे में आवंटन के उद्देश्यों के लिए न्यूनतम सीमा शैक्षिक योग्यता विकसित करना अनिवार्य रूप से एक नीतिगत मामला था जिसे केंद्र शासित प्रदेश ने वर्तमान मामले में वैध रूप से प्रयोग किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आज तक किए गए आवंटन में बड़े पैमाने पर व्यवधान होगा और हस्तक्षेप करना व्यर्थ होगा क्योंकि कई अन्य उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन नहीं किया होगा और जो अपीलकर्ता से बेहतर हो सकते हैं, उन्हें विचार से बाहर रखा जाएगा।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. विवरणिका के अलावा, जिसके प्रासंगिक उद्धरण प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर चर्चा करने से पहले निर्धारित किए गए थे, प्रचलित खेल कोटे (नीति² में सन्निहित) के प्रासंगिक प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। नीति के पैरा 2 में कहा गया है कि इस खेल श्रेणी का लाभ उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो "चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों से अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और जिन्होंने स्नातक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम दो साल तक चंडीगढ़ के स्कूलों या कॉलेजों में अध्ययन किया है।" नीति में आगे यह निर्धारित किया गया कि प्रमाण पत्रों की योग्यता, यानी खेल प्रमाण पत्रों को ए, बी, सी और डी के रूप में और अवरोही क्रम में उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रेड ए में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया या जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप, टूर्नामेंट और उच्चतम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा आयोजित चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ग्रेड बी में ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने विश्व विश्वविद्यालय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ग्रेड ए के अलावा अन्य खेलों में भाग लिया, जिसमें एशियाई फेडरेशन कप सहित कम से कम 10 टीमों ने भाग लिया; स्कूल गेम्स या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राज्य महासंघ, अखिल भारतीय

2 दिनांकित 05.05.2003 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया।

संयुक्त विश्वविद्यालय टीम आदि में पहले तीन स्थान प्राप्त किए। ग्रेड सी ने वरिष्ठनागरिकों/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं/महासंघ कप में भागीदारी को सूचीबद्ध किया; जूनियर राष्ट्रीय महासंघ अर्थात् राष्ट्रीय विद्यालय खेल, राष्ट्रीय विद्यालय खेल में भाग लेने वाली केवीएस टीमों; मान्यता प्राप्त चंडीगढ़ विद्यालय खेल में पहले तीन स्थान (बशर्ते कम से कम 7 टीमों ने भाग लिया हो) और ऐसी कई अन्य खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लिया। ग्रेड डी ने मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप/राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी; राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में भागीदारी आदि को सूचीबद्ध किया।

12. नीति में आगे यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित संस्थान द्वारा राज्य रैंकिंग पर विचार किया जाएगा और मानदंडों को निम्नलिखित क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा: किसी भी प्रतियोगिता में रिकॉर्ड धारक; विजेता; उपविजेता; तीसरा स्थान धारक; भाग लेने की संख्या; भाग लेने वाले विषयों की संख्या)। अन्य मानदंड भी लिखे गए थे। नीति के अनुसार, खेल श्रेणीकरण में उप-कनिष्ठ श्रेणी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को शामिल नहीं किया गया है और यह कि राज्य/वरिष्ठ/कनिष्ठ/अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिता या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं आदि में सात या उससे अधिक प्रतिभागियों के साथ या राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दस राज्य विश्वविद्यालयों, यानी वरिष्ठ, कनिष्ठ और सभी विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सात या उससे अधिक प्रतिभागियों के साथ हासिल किए जाने पर ही प्राप्त किए गए स्थान होंगे। इसके अलावा, नीति में यह निर्धारित किया गया था कि आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा और संबंधित विषय में फील्ड टेस्ट भी दिए जाएंगे, ताकि वे अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रशंसापत्रों/प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का आकलन कर सकें।

13. वर्तमान मामले में 75 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता मानदंड को उचित ठहराते हुए उस नोट को पुनः प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा जिसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की शर्तों के आधार पर

प्रतिवादी की प्रवेश नीति से निपटने के लिए, नोट में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है:

-- "पी.ई.सी वर्ष 2017 तक संयुक्त प्रवेश समिति (जे. ए. सी.) चंडीगढ़ में भाग ले रहा था। सामान्य और खेल श्रेणी के लिए जे.ए.सी 2017 की पात्रता मानदंड समान था यानी 12 वीं कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। तैयार संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न करें।

-- कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी), खिलाड़ियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/पोते-पोतियों के लिए पी. ई. सी. द्वारा पालन किए जाने वाले पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं-

प्रवेश का वर्ष	माध्यम से प्रवेश	प्रवेश एजेंसी द्वारा स्थापित 10+2 के प्रासंगिक मानदंड	पी.ई.सी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले 10+2 के प्रासंगिक मानदंड	टिप्पणियां
2017-18	जे.ए.सी चंडीगढ़	>= 60 प्रतिशत	> =60 प्रतिशत	प्रवेश एजेंसी के समान
2018-19	जोसा/सी.एस.ए.बी	> =75 %	> =75 %	प्रवेश एजेंसी के समान
2019-20	जोसा/सी.एस.ए.बी	> =75%	>= 75 %	प्रवेश एजेंसी के समान
2020-21	जोसा/सी.एस.ए.बी	10+2 उत्तीर्ण	10+2 उत्तीर्ण	प्रवेश एजेंसी के समान
2021-22	जोसा/सी.एस.ए.बी	10+2 उत्तीर्ण	10+2 उत्तीर्ण	प्रवेश एजेंसी के समान
2022-23	जोसा/सी.एस.ए.बी	10+2 उत्तीर्ण	10+2 उत्तीर्ण	प्रवेश एजेंसी के समान
2023-24	जोसा/सी.एस.ए.बी	> =75 %	> =75%	प्रवेश एजेंसी के समान

- प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी), खिलाड़ियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/पोते-पोतियों की परामर्श के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.07.2023 थी और आगे की प्रक्रिया जारी है।
- कि तत्काल रिट याचिका केवल 13.07.2023 पर प्रारंभिक सुनवाई के लिए आ रही है, जब प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और इस प्रकार, याचिका पर रोक लगा दी गई है।
- कि विवरण पत्रिका पुण्यमय है और इस स्तर पर, यदि मानदंड बदल दिए जाते हैं, तो पूरी प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो जाएगी और यह पटरी से उतर जाएगी।
- शैक्षणिक सत्र 31.07.2023 से शुरू होने वाला है और उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत व्याख्यानों में भाग लेना होगा।"

14. अब यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में निहित है कि समानता के सिद्धांत के विभिन्न और स्तरित आयाम हैं, जिनमें से एक यह है कि अनुच्छेद 14 के तहत, "समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। असमानताओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उचित वर्गीकरण का गठन प्रत्येक मामले के तथ्यों, कानून द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ, बोधगम्य अंतर के अस्तित्व पर निर्भर करना चाहिए जिसके कारण व्यक्तियों या चीजों को एक वर्ग के रूप में समूहीकृत किया गया है और उन लोगों को छोड़ दिया गया है जो बोधगम्य अंतर को साझा नहीं करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।" (संदर्भ मनीष कुमार बनाम भारत संघ (यू.ओ.आई) और अन्य³)

15. इस अदालत ने आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य⁴ में बताया कि उचित वर्गीकरण को कैसे लागू किया जाना चाहिए:

3 2021 (14) एससीआर 895

4 2002 (2) एससीआर 649

"6. कानून के समक्ष समानता की अवधारणा में सभी के बीच पूर्ण समानता का विचार शामिल नहीं है, जो एक भौतिक असंभवता हो सकती है। अनुच्छेद 14 जो कुछ भी गारंटी देता है वह उपचार की समानता है न कि समान उपचार की। समान कानूनों के संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि सभी कानून समान होने चाहिए। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए और समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कानून के सामने समानता का मतलब यह नहीं है कि जो चीजें अलग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे वे समान हों। यह सच है कि अनुच्छेद 14 में आदेश दिया गया है कि समान रूप से स्थित लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन कितनी असमानता लोगों को समान रूप से व्यवहार करने के लिए अयोग्य बनाएगी, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। एक विधायिका, जिसे मानव संबंधों की अनंत विविधता से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना होता है, के पास विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए और उस उद्देश्य के लिए उसके पास व्यक्तियों और चीजों के चयन या वर्गीकरण की बड़ी शक्तियां होनी चाहिए जिन पर ऐसे कानून काम करते हैं। केवल भेदभाव या व्यवहार की असमानता समान संरक्षण खंड के अवरोध के भीतर भेदभाव के बराबर नहीं है। राज्य के पास हमेशा उस विशेष विषय के लिए प्रासंगिक तर्कसंगत भेद के आधार पर वर्गीकरण करने की शक्ति होती है जिससे निपटा जाना है। अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए हैं और (ii) उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। आवश्यक बात यह है कि वर्गीकरण के आधार और अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। जब किसी कानून को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो सबसे पहले कानून में अंतर्निहित नीति और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का पता लगाना आवश्यक है। नीति और अधिनियम के उद्देश्य का पता लगाने के बाद, अदालत को वैधता की जांच करने के लिए एक दोहरी परीक्षा लागू करनी होगी, परीक्षण यह है कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत है और एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है जो व्यक्तियों या चीजों को एक साथ अलग करता है जो समूह से बाहर हैं, और क्या भेदभाव के आधार का इसकी घोषित नीति और उद्देश्यों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध या संबंध है। इस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को निरस्त करने के लिए, असमानता एक ही विधान के तहत या कानूनों के एक ही समूह के तहत उत्पन्न होनी चाहिए, जिन्हें एक साथ एक अधिनियम के रूप में माना जाना चाहिए। एक ही

विषय के संबंध में दो अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा किए गए दो अलग-अलग अधिनियमों के परिणामस्वरूप असमानता अनुच्छेद 14 के तहत हमले के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा⁵ में यह भी कहा गया है कि "प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य" केवल असमानताओं को अंधाधुंध रूप से थोपने का ढोंग नहीं होना चाहिए और वर्गीकरण को "मनमाना या बेतुका" नहीं माना जाना चाहिए।^{वेकटेश्वर थिएटर बनाम ए. पी.⁶} राज्य में निर्णय एक ऐसा निर्णय है जिसमें इस अदालत ने बताया कि भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है, यदि गैर-समान व्यक्तियों को समान माना जाता है, तो इस प्रकार:

"जिस तरह व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार में अंतर भेदभाव की ओर ले जाता है, उसी तरह भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है यदि असमान व्यक्तियों, यानी अलग स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए।.....असमान वस्तुओं, लेन-देन या व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करने वाले कानून की भेदभावपूर्ण के रूप में निंदा की जाएगी यदि कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध का अभाव है।

16. रूप चंद अदलखा बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण⁷ में टिप्पणियाँ बहुत ही बोधगम्य हैं, और वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं; अदालत ने कहा था कि "वर्गीकरण की प्रक्रिया अपने आप में असमानता का उत्पादक है और उस अर्थ में समानता के विरोधी है। यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से वैध होगी यदि यह पहले से मौजूद असमानता को पहचानती है और ऐसी पहले से मौजूद असमानता के प्रभावों को कम करने में सहायता करती है। लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में असमानता को उत्पन्न या बढ़ा नहीं सकती है "और चेतावनी दी कि वर्गीकरण के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देना" या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का कोई भी चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से लेख को इसकी बहुमूल्य सामग्री से वंचित कर सकता है और वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा समानता के सिद्धांत को बदलने में

5 1974 (1) एससीआर 771

6 1993 (3) एससीआर 6169.

7 1988 सप्लीमेंट (3) एससीआर 353

समाप्त हो सकता है "इस प्रकार वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए" समानता की बहुमूल्य गारंटी "को केवल रेत की रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। "दीपक सिब्बल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय⁸ में उचित वर्गीकरण परीक्षा के आवेदन ने एक नियम को अमान्य कर दिया, जिसने निजी प्रतिष्ठानों के अयोग्य कर्मचारियों को अयोग्य घोषित कर दिया और शाम के विधि महाविद्यालय में सरकारी विभागों और संस्थानों में उम्मीदवारों के प्रवेश को सीमित कर दिया। वर्गीकरण की निंदा करते हुए, इस अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय "शाम की कक्षाएं शुरू करने के उद्देश्य से भटक गया था। इसका उद्देश्य शाम की कक्षाओं में निजी कर्मचारियों सहित सामान्य रूप से कर्मचारियों को समायोजित करना था जो अपने रोजगार के कारण सुबह की कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे। "विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया औचित्य, कि सरकारी कर्मचारियों के पास स्थायी नौकरी या पद था, शाम के कानून पाठ्यक्रम को खोलने के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक माना गया था।

17. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो⁹ में इस अदालत ने सार्वजनिक रोजगार में स्थिति के आधार पर एक वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया और अमान्य घोषित कर दिया, यह बताते हुए कि यह अंतर्निहित कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है, अर्थात् भ्रष्टाचार का मुकाबला करना:

"59. हमें ऐसा लगता है कि सरकारी सेवा में स्थिति के आधार पर धारा 6-ए में किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के तहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई खोजने के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो पीसी अधिनियम, 1988 के तहत एक अपराध के बराबर है। क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर ठोस अंतर हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अपनी स्थिति या पद की परवाह किए बिना, भ्रष्ट लोक सेवक लोक शक्ति के भ्रष्टकर्ता हैं। भ्रष्ट लोक सेवक, चाहे वे उच्च हों या निम्न, एक ही पंख के पक्षी हैं और उन्हें जांच और जांच की प्रक्रिया का समान रूप से सामना करना चाहिए। सेवा

8 1989 (1) एससीआर 689

2014 (9) एससीआर 283

में पद या स्थिति के आधार पर, लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के बराबर के आरोप हैं।"

ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के वस्तुनिष्ठ अनुप्रयोग पर, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि खेल कोटा यानी प्रवेश का 2 प्रतिशत शुरू करने का उद्देश्य उन लोगों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना था जिन्होंने परिभाषित प्रतिस्पर्धी खेलों में एक निश्चित स्तर की निर्धारित प्रवीणता और उपलब्धि हासिल की। इस कोटे की शुरुआत शैक्षणिक संस्थानों में खेल और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक निश्चित न्यूनतम पात्रता मानक या मानदंडों के सेट को निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर कार्य करता है। इस प्रकार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जगतप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय¹⁰ में योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 15 प्रतिशत प्राप्त करने के कट ऑफ पात्रता मानक के प्रिस्क्रिप्शन को बरकरार रखा:

याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए विवरण पत्रिका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि कुल 15 अंकों की न्यूनतम कट-ऑफ होगी। उत्तरदाताओं-विश्वविद्यालय ने केवल ऐसे मानदंड पेश किए हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं जो एक ऐसे छात्र के लिए आवश्यक होगा जो अंततः एक इंजीनियर बनना चाहता है। अमरदीप सिंह सहोता के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ऐसे छात्र हैं जो अंततः मानवता की सेवा करेंगे। खेल में उत्कृष्टता एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक मानक बनाए रखने की आवश्यकता है।"

हालाँकि, खेल कोटा शुरू करने का उद्देश्य शैक्षणिक योग्यता को समायोजित करना नहीं है, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग है: संस्थान, विश्वविद्यालय और अंततः देश में खेलों को बढ़ावा देना। अन्य में, विश्वविद्यालय नर्सरी या खिलाड़ियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो राज्य, राष्ट्रीय,

10 (2004) 138 पीएलआर 896

अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ ही, राज्य या शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम पात्रता शर्त पर जोर दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शर्त आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से सामान्य (या खुली श्रेणी) उम्मीदवारों के लिए लागू होनी चाहिए। बाद के प्रकार के मानदंड मेधावी खिलाड़ियों को बाहर करते हैं, और कम (शैक्षणिक रूप से) मेधावी खिलाड़ियों को एक नुकसानदेह स्थिति में रखते हैं, क्योंकि वे उच्च शैक्षणिक योग्यता के खुले श्रेणी के उम्मीदवारों के मानदंड को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, यह बहुत संभव है कि एक खिलाड़ी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और जारी है, और जिसने कुश्ती में एक या दो पदक जीते हैं, उसे योग्यता परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी (लेकिन जो कभी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा है) के पहलवान की संभावना में पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। यह ठीक यही परिणाम है जिसे इस अदालत ने चेतावनी दी थी कि एक समान मानदंड का "असमान अनुप्रयोग" होगा, अंतर्निहित मतभेदों की परवाह किए बिना एक लकड़ी की समानता, जिसे अनुच्छेद 14 अस्वीकार करता है और मना करता है।

18. अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का इस तथ्य से भी समर्थन होता है कि 2023 की प्रवेश को नियंत्रित करने वाली खेल नीति, विस्तार से सावधानीपूर्वक विकसित की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल में प्रदर्शन, शैक्षणिक योग्यता के बजाय, 2 प्रतिशत खेल कोटे को भरने के लिए आवेदन करने के लिए चुना गया मानदंड था। एक अन्य कारण जो इस अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है कि भेदभाव हुआ है, क्योंकि खेलों के संबंध में भी, राज्य ने अनुच्छेद 15 (4) के तहत ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण का आनंद लेने वालों के लिए मानदंड को कम कर दिया है। इस तरह की स्थिति में, राज्य के लिए यह खुला था कि वह अन्य उम्मीदवारों के लिए भी खेल कोटे के लिए पात्रता मानदंड को कम करे; इसलिए व्यवहार में असमानता गंभीर है। इसके अलावा, रिकॉर्ड इंगित करता है कि शैक्षणिक वर्षों 2018-19, 2019-20 और 2023-24 को छोड़कर, पिछले सभी वर्षों के लिए निर्धारित पात्रता कम थी; वास्तव में, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए, मानदंड "10+2 पास" था। अंत में, खेल नीति स्वयं इस बात को रेखांकित करती है कि कोटा उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो "चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों से अपनी

योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं" या जिन्होंने पिछले दो वर्षों से चंडीगढ़ में अध्ययन किया था। सभी उम्मीदवारों से संबंधित विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए 2023 की खेल नीति में निर्धारित एक निश्चित पात्रता मानक (जिसका उल्लेख किया गया है) या संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता अंकों को पूरा करने की आवश्यकता एक समान मानक के प्रिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से अलग है, जो ऐसी न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है। अतः न्यूनतम 75 प्रतिशत पात्रता शर्त लागू करना खेल कोटा लागू करने के उद्देश्य को कम नहीं करता है, बल्कि इसके लिए विनाशकारी है; मानदंड, उस अर्थ में उद्देश्य को विकृत करता है और भेदभावपूर्ण है; इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड के खिलाफ आता है।

19. उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है कि योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के आधार पर याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों का बहिष्कार अनुचित और भेदभावपूर्ण था। इस तरह के मानदंड को प्रभावी बनाने वाले खंडों के संदर्भ और समावेश को अप्रवर्तनीय और शून्य माना जाता है। यह अदालत इस तथ्य से अवगत है कि एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर प्रवेश के लिए आवंटन पूरा कर लिया गया है। इस अदालत के अंतरिम आदेश, दिनांक 08.08.2023 द्वारा, प्रतिवादी को बची हुई सीट (सीटों) को भरने से रोक दिया गया था, जिसे 10.08.2023 पर निर्धारित अंतिम दौर (प्रवेश प्रक्रिया) के बाद भरा जाना था। निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि शेष सीट या सीटें चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की खेल नीति में उल्लिखित मानकों के आवेदन द्वारा भरी जाएंगी, जैसा कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन किया गया था ताकि उन उम्मीदवारों की अंतर खेल योग्यता निर्धारित की जा सके जिन्होंने आवेदन किया था, लेकिन जिनकी उम्मीदवारी योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के कारण अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी। हालाँकि इन उम्मीदवारों को तुरंत पिछले शैक्षणिक वर्ष के मानदंड के संदर्भ में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, जो शेष खेल कोटा सीट (सीटों) के लिए लागू होती है। साथ ही, जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है और उन्हें प्रवेश दिया गया है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। खेल कोटे में शेष रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया दो सप्ताह के

भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस निर्णय में जो कुछ भी कहा गया है, उसके परिणामस्वरूप अन्य (गैर-खेल) श्रेणियों में उम्मीदवारों के प्रवेश को अमान्य कर दिया जाएगा।

20. परिणामी रूप से, विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। इन परिस्थितियों में, लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

..... J.

[S.RAVINDRA BHAT]

..... J

[ARVIND KUMAR]

नई दिल्ली

9 अगस्त, 2023

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा